प्रिकॉशन डोज शुरू किए जाने का एलान

ओमिक्रoन के रूप में उभर आए नए खतरे को देखते हुए इन दोनों कदमों की जरूरत महसूस की जा रही थी। वैक्सिनेशन के इस नए फेज की शुरुआत तब हो रही है, जब टीकाकरण मुहिम को एक साल पूरा हो रहा है।

राधा शर्मा।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए आखिर बच्चों के लिए वैक्सीन के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित सीनियर सिटिजंस के लिए प्रिकॉशन डोज शुरू किए जाने का एलान कर दिया। ओमिक्रॉन के रूप में उभर आए नए खतरे को देखते हुए इन दोनों कदमों की जरूरत महसूस की जा रही थी। वैक्सिनेशन के इस नए फेज की शुरुआत तब हो रही है, जब टीकाकरण मुहिम को एक साल पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस एक साल की उपलब्धियां भी बताईं।

उन्होंने जानकारी दी कि इस अवधि में देश की 61 फीसदी वयस्क आबादी को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है और 90 फीसदी वयस्क आबादी एक डोज ले चुकी है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस आसानी से बच्चों में भी फैल रहा है, उसे देखते हुए सिर्फ वयस्क आबादी का हिसाब ज्यादा आश्वस्त करने वाला नहीं लगता। दूसरी बात यह कि इस वयस्क आबादी में भी 39 फीसदी को पूरी तरह वैक्सीन के सुरक्षा दायरे में नहीं माना जा सकता। ऐसे में विशेषज्ञों के सामने स्वाभाविक ही दुविधा की स्थिति बन गई थी। उन्हें तय करना था कि सरकार का जोर किस पर होना चाहिए, पहले समूची आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का अभियान पूरा कर लेना ठीक होगा ताकि सभी न्यूनतम सुरक्षा के घेरे में आ जाएं या फिर अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा प्रिकॉशन डोज देने में लगाते हुए यह काम भी साथ–साथ चलाना चाहिए।

आखिर विभिन्न देशों से मिल रहे आंकड़ों और विशेषज्ञों की सलाहों के अनुसार फैसला हुआ कि तय प्रक्रिया के मुताबिक टीकाकरण अभियान यथासंभव तेजी से जारी रखते हुए भी उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जाना जरूरी है, जिन्हें ज्यादा खतरा है। इसी नीति के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को प्रिकॉशन डोज देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही बच्चों में ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे के मद्देनजर उन्हें भी जल्द से जल्द टीके दिलाने का फैसला हुआ है, जो उचित ही है। इसी संदर्भ में यह भी जरूरी है कि दो टीकों के बीच अंतर कम करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। बदले हालात में इस अंतराल को बड़ा बनाए रखने का मतलब यह होगा कि एक डोज ले चुके लोग ज्यादा समय तक टीके की पूर्ण सुरक्षा हासिल करने से वंचित रहेंगे।

पहली नजर में यह स्थिति संक्रमण का जोखिम बढ़ाने वाली लगती है। हालांकि इस मामले में भी यह तो विशेषज्ञ ही तय कर सकते हैं कि दो टीकों के बीच का अंतराल कितना कम किया जाए जिससे इसकी क्षमता प्रभावित न हो। कुल मिलाकर, प्रिकॉशन डोज और बच्चों के लिए टीके का यह फैसला ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने में सहायक जरूर होगा, मगर निर्णायक मोर्चा आम लोगों की सावधानी का स्तर ही बना रहने वाला है।

आदर्श गृहस्थ

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

दरअसल वह कृत्रिम है और बार–बार उसपर प्रश्न उठाये गये हैं। जबकि कुछ लोग, धर्मशास्त्र में धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष कानूनों के बीच अंतर रखा गया है ऐसा पक्ष लेते हैं। धर्मशास्त्र हिन्दू परंपरा में महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि– एक, यह एक आदर्श गृहस्थ के लिए धार्मिक नियमों का स्रोत है, तथा दूसरे, यह धर्म, विधि, आचारशास्त्र आदि से संबंधित हिंदू ज्ञान का सुसंहत रूप है। पांडुरंग वामन काणे, सामाजिक सुधार को समर्पित एक महान विद्वान्न ने इस पुरानी परंपरा को जारी रखा है। उनका धर्मशास्त्र का इतिहास, पाँच भागों में प्रकाशित है, प्राचीन भारत के सामाजिक विधियों तथा प्रथाओं का विश्वकोश है। इससे हमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। धर्मसूत्रों में वर्णाश्रम–धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा के कर्त्तव्य आदि का विधान है।

संपादकीय

संवाद पर हो जोर

नई नीति में यह ठीक कहा गया है कि अब पाकिस्तान कश्मीर के कारण भारत से बातचीत बंद नहीं करेगा। लेकिन तब भी वह राग कश्मीर अलापता ही रहेगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अब कश्मीर में कोई रुचि नहीं है। चीन भी उस पर चुप ही रहता है। लेकिन हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को घसीटने से पाकिस्तान बाज नहीं आता। अच्छा हो कि इमरान सरकार इस मुद्दे पर भारत सरकार से सीधे संवाद की पहल करे। पाकिस्तान के जितने भी राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और बुद्धिजीवियों से पिछले 50 साल में मेरा संवाद हुआ है, उनसे मैंने यही कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का यह कथन आप भूल जाइए कि कश्मीर लेने के लिए आप हजार साल तक भारत से लड़ते रहेंगे। कश्मीर का हल लात से नहीं, बात से ही होगा। कश्मीर के बहाने पाकिस्तान ने सारी दुनिया से बदनामी मोल ले ली। वह आतंक और फौजी तानाशाही का गढ़ बन गया। भारत के साथ उसकी दुश्मनी खत्म हो जाए तो उसे अमेरिका या चीन जैसे राष्ट्रों का चरणदास नहीं बनना पड़ेगा और पाकिस्तान के लोग भारतीयों की तरह लोकतंत्र और खुशहाली में जी सकेंगे।

इमरान सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की जो घोषणा की है, उसमें आर्थिक सुरक्षा का स्थान सबसे ऊंचा है। इसीलिए उसमें साफ–साफ कहा गया है कि पाकिस्तान अब सामरिक सुरक्षा के बजाय आर्थिक सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।

डर से उपजी नीति

वेदप्रताप वैदिक।।

पाकिस्तान ने 14 जनवरी को पहली बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की है। जब से पाकिस्तान बना है, ऐसी घोषणा पहले कभी नहीं की गई। इसका अर्थ यह नहीं है कि पाकिस्तान की कोई सुरक्षा नीति ही नहीं थी। यदि ऐसा होता तो वह अपने पड़ोसी भारत के साथ कई युद्ध कैसे लड़ता और आतंकवाद को अपनी स्थायी रणनीति क्यों बनाए रखता? परमाणु बम तो वैसी स्थिति में बन ही नहीं सकता था। अफगानिस्तान के साथ वह कई–कई बार युद्ध के कगार पर कैसे पहुंच जाता?

अफगानिस्तान के सशस्त्र गिरोहों को पिछले 50 साल से वह शरण क्यों देता रहता? किसी सुरक्षा नीति के बिना अमेरिका के सैन्य–गुटों में वह शामिल क्यों हो गया था? पहले अमेरिका और अब चीन का पिछलग्गू बनने के पीछे उसका रहस्य क्या है? बस वही, सुरक्षा नीति! सुरक्षा किससे? भारत से। जब से पाकिस्तान बना है, उसके दिल में यह डर बैठा हुआ है कि भारत उसका वजूद मिटा देगा। भारत उसे खत्म करके ही दम लेगा। भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। उसे लगता है कि वह पाकिस्तान के कम से कम चार टुकड़े करना चाहता रहा है। एक पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा बलूचिस्तान और चौथा

पख्तूनिस्तान। तो पाकिस्तान भी भारत के टुकड़े करने की कोशिश क्यों न करे? उसकी कोशिश कश्मीर, खालिस्तान, असम, नगालैंड और मिजोरम को खड़ा करने की रही है। तू डाल–डाल तो हम पात–पात! नहले पर दहला मारने की यही नीति पाकिस्तान की सुरक्षा नीति रही है। भारत ने परमाणु बम बनाया तो पाकिस्तान ने भी जवाबी बम बना लिया।

ऐसी सुरक्षा नीति की भला कोई सरकार घोषणा कैसे कर सकती थी? उसे जितना छिपाकर रखा जाए, उतना ही अच्छा। लेकिन उसके नतीजों को आप कैसे छिपा सकते हैं? पिछले 7–8 दशकों में वे नतीजे सारी दुनिया के सामने अपने आप आने लगे। अपने आप को तुर्रम खां बताने वाले पाकिस्तान के फौजी तानाशाहों, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को मालदार मुल्कों के आगे भीख का कटोरा फैलाए खड़े रहना पड़ता रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का जो गुब्बारा 1947 में फुलाया था, उसकी हवा आज तक निकली पड़ी है। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान एक आदर्श इस्लामी राष्ट्र क्या बनता, वह दक्षिण एशिया के सबसे पिछड़े राष्ट्रों में शुमार हो गया।

अब इमरान सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की जो घोषणा की है, उसमें आर्थिक सुरक्षा का स्थान सबसे ऊंचा है। इसीलिए उसमें साफ–साफ कहा गया है कि पाकिस्तान अब सामरिक सुरक्षा के बजाय आर्थिक सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। यदि वह सचमुच ऐसा करेगा तो बताए कि उसका रक्षा–बजट कुल बजट का 16 प्रतिशत क्यों है? यदि अपने इस 9 बिलियन डॉलर के फौजी बजट को वह आधा कर दे तो क्या बचे हुए पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तानियों की शिक्षा, चिकित्सा और भोजन की कमियों को पूरा करने में नहीं किया जा सकता? इस नई सुरक्षा नीति की घोषणा के बाद देखना है कि अब उसका बजट कैसा आता है। यह नई सुरक्षा नीति कोई रातोरात बनकर तैयार नहीं हुई है। पिछले सात साल से इस पर काम चल रहा है, नवाज शरीफ के जमाने से। मियां नवाज के विदेश मंत्री और सुरक्षा सलाहकार रहे बुजुर्ग नेता सरताज अजीज ने इस नई नीति पर काम शुरू किया था।

अष्टयोग-5018

	3	1		6	7	
4	28		25		36	
2	5		3		7	4
	34		35	5	33	
3		7	6			1
7	34	5	42	3	30	
1				7	2	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5017 का हल

5	3	6	4	1	7	2
4	28	2	25	2	36	7
2	5	1	3	6	7	4
6	28	5	35	3	39	6
3	2	4	6	7	5	1
7	32	3	42	5	32	5
1	5	7	6	4	2	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

चीन के साथ मिलकर बहिष्कार

मोहन। भारत ने तो अफगानिस्तान के लिए 50 हजार टन अनाज और दवाइयां भिजवाने की घोषणा की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उसे काबुल पहुंचाने का रास्ता नहीं खोला है। भारत ने अफगानिस्तान पर बात करने के लिए पड़ोसी राष्ट्रों की बैठक में पाकिस्तान को भी बुलाया था। लेकिन उसने चीन के साथ मिलकर उसका बहिष्कार कर दिया। अफगान–संकट ने तो ऐसा मौका पैदा कर दिया था कि उसका मिल–जुलकर समाधान करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो सकती थी। यदि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से समृद्ध होना है तो उसे दक्षिण और मध्य एशिया के बीच एक सेतु की भूमिका तुरंत स्वीकार करनी चाहिए। यदि वह एक सुरक्षित पुल बन जाए तो मध्य एशिया के गैस, तेल, लोहा, तांबा, यूरेनियम आदि से भारत और पाकिस्तान मालामाल हो सकते हैं। अभी तो भारत–पाक व्यापार पर भी तालाबंदी लगी हुई है। सचमुच आपका यही इरादा है तो अभी भी आपने आधी नीति छिपाकर क्यों रखी है?